

केंद्र द्वारा समलैंगिक विवाह का वरिध

प्रलिस के लयः

नवतेजी सहि जौहर केस, मौलिक अधकार, परसनल लॉ, LGBTQIA+ के अधकार ।

मेन्स के लयः

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तरक, समलैंगिक विवाह के वरिध तरक ।

चर्चा में क्यों?

केंद्र ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) में [समलैंगिक विवाह](#) का वरिध करते हुए कहा है कि **जैविक पुरुष और महिला के बीच विवाह भारत में एक पवत्रि मलिन, संस्कार और परंपरा है ।**

- **भारत के मुख्य न्यायाधीश** के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाहों को मान्यता दयि जाने की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की [संविधान पीठ](#) को भेज दयि ।

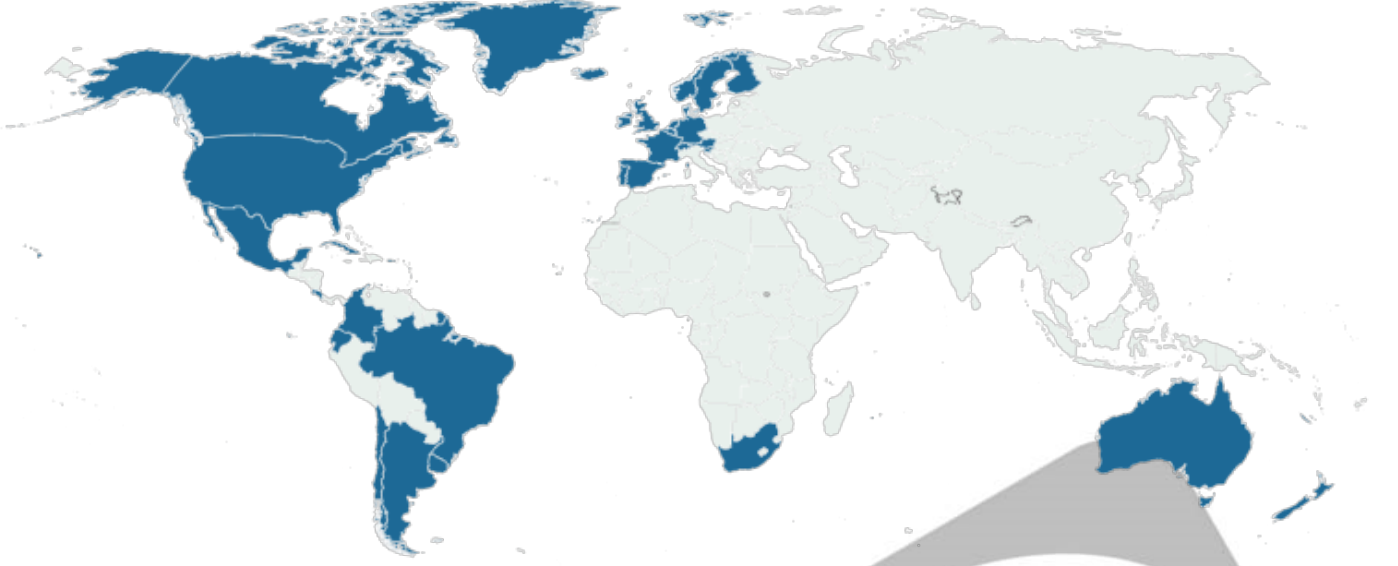
समलैंगिक विवाह के संदर्भ में सरकार का पक्ष:

- सरकार ने तरक दयि कि न्यायालय ने [नवतेज सहि जौहर बनाम भारत संघ](#) के 2018 के अपने फैसले में समलैंगिक व्यक्तियों के बीचयौन संबंधों को केवल अपराध की श्रेणी से बाहर कयि था, न कि इस 'आचरण' को वैध ठहराया था ।
 - न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत [जीवन और गरमा के मौलिक अधकार](#) के हसिसे के रूप में स्वीकार नहीं कयि ।
- सरकार का तरक है कि **विवाह रीत-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर नरिभर करता है ।**
 - समलैंगिक विवाह की तुलना पति, पत्नी और बच्चों की भारतीय परिवार इकाई की अवधारणा से नहीं की जा सकती ।
- [संसद](#) ने देश में केवल एक पुरुष और महिला के मलिन को मान्यता देने हेतु **विवाह कानूनों का प्रारूप तैयार कयि है ।**
 - समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह का पंजीकरण मौजूदा [व्यक्तगत, साथ ही संहिताबद्ध कानूनी प्राधानों का उल्लंघन होगा ।](#)
 - [वशिष विवाह अधनियम, 1954](#) उन युगल के लयि विवाह का नागरिक अधकार प्रदान करता है जो अपने व्यक्तगत कानून के तहत शादी नहीं कर सकते ।
- सरकार ने तरक दयि कि इस मानदंड से कोई भी परिवर्तन केवल **वधायिका के माध्यम से कयि जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं ।**

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तरक:

- **कानून के तहत समान अधकार और संरक्षण:** यौन अभविन्यास की परवाह कयि बना, हर कसिी को विवाह करने और परिवार बसाने का अधकार है ।
 - समान-लगि वाले जोड़ों के पास वपिरीत-लगि जोड़ों के **समान कानूनी अधकार और सुरक्षा** होनी चाहयि ।
 - समलैंगिक विवाह की गैर-मान्यता भेदभाव युक्त थी जो [LGBTQIA+ जोड़ों की गरमा और आत्म-संतुष्टि पर प्रहार करती थी ।](#)
- **परिवारों और समुदायों को मज़बूती प्रदान करना:** विवाह संस्कार जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करता है । समान-लगि वाले जोड़ों को विवाह की अनुमति दयि जाने से उनकी स्थरिता और सुरक्षा को बढ़ावा देकर परिवारों एवं समुदायों को मज़बूती प्रदान की जा सकती है ।
- **वैश्विक स्वीकृति:** वशिष के कई देशों में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता प्राप्त है, और एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधकार से वंचित करना **वैश्विक सिद्धांतों के खिलाफ** है ।
- **समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले देश:**
 - **133 देशों में** समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दयि गया है, लेकिन उनमें सेकेवल **32 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी**

मान्यता प्राप्त है।



समलैंगिक विवाह के खिलाफ तर्क:

- **धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ:** कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के मध्य ही होना चाहिये।
 - उनका तर्क है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषा को बदलना उनके विश्वासों और मूल्यों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
- **प्रजनन:** कुछ लोग तर्क देते हैं कि विवाह का प्राथमिक उद्देश्य संतानोत्पत्ति है और समलैंगिक जोड़ों के जैविक बच्चे नहीं हो सकते।
 - इसलिये उनका मानना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है।
- **कानूनी मुद्दे:** ऐसी चर्चाएँ हैं कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएँ उत्पन्न होंगी जैसे कि विरासत, कर और संपत्ति का अधिकार।
 - कुछ लोगों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिये सभी वधियों और वनियमों को परिवर्तित करना बहुत कठिन होगा।

आगे की राह

- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** भारत विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के साथ सांस्कृतिक विविधता वाला देश है।
 - समलैंगिक विवाह पर किसी भी वधायी या न्यायिक निर्णय को लेकर विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर विचार किया जाना चाहिये, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा हो।
- **सामाजिक स्वीकृति और शिक्षा: LGBTQIA+ समुदाय** की सामाजिक स्वीकृति के मामले में भारत को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
 - वधि लैंगिकता की स्वीकृति और समझ को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, साथ ही समलैंगिक विवाह पर विचार किया जाना चाहिये।
- **अंतरराष्ट्रीय दायित्व:** भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है, जसिके लिये LGBTQIA+ समुदाय सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।
 - कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, यह अनिवार्य है कि भारत सभी व्यक्तियों के लिये समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिये उनके यौन रूचा की परवाह किये बिना इसे वैधता प्रदान करे।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

Q. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25

(d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (b)

स्रोत: द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/centre-opposes-same-sex-marriage>

